राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 161

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 19 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस बोबडे

>>3

सरोकार

मददगार अधिकारी को दुआएं देते नहीं थकतीं ज्ञानवती

फतेहपुर : दुर्घटना में घायल विधवा ज्ञानवती की नौकरी गई तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी इलाके के बैंक प्रबंधक ने अपने दायित्व को विस्तार देते हुए न केवल डेयरी के लिए लोन दिलाकर दूध का कारोबार शुरू कराया, वरन एक परिवार का भविष्य सुरक्षित कर दिखाया। (पेज-11)

जागरण विशेष

इनके तो रोम-रोम में सुशोभित प्रभु श्रीराम का नाम...

बिलासपुर : न मंदिर, न मूर्ति, न ग्रंथ। बस राम नाम ही इनके लिए पर्याप्त है। प्रभु के नाम को इन्होंने रोम-रोम में सुशोभित किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में रामनामियों की आबादी अब नाममात्र को रह गई है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

चिट फंड संशोधन विधेयक पर भिड़े बंगाल के सांसद

नई दिल्ली : लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही चिट फंड संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हो गई। देश में चिट फंड का काम करने वाली कंपनियों पर कड़ी निगरानी के लिए पेश इस बिल पर चर्चा के दौरान बंगाल से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सांसदों के बीच वाद-विवाद होने लगा। लोस अध्यक्ष ओम बिरला को बीच-बचाव करना पड़ा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

कश्मीर घाटी में सशर्त इंटरनेट बहाली की तैयारी

जम्मू : कश्मीर घाटी में हालात सामान्य होने के साथ प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बहाली की ओर कदम बढ़ा दिया है। पहले चरण में सशर्त ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल की जाएंगी। पुलिस जांच के बाद ही सरकारी और निजी संस्थानों को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। राज्य के पुनर्गठन से पूर्व ही जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

निवेश ही खेती को जलवायु परिवर्तन से बचाएगा : गेट्स

नई दिल्ली : जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कृषि क्षेत्र में गंभीर चुनौतियां खड़ी होने लगी हैं। खासकर दुनियाभर के छोटे किसानों की मुश्किलें और बढ़ी हैं। अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स ने कहा कि सटीक आंकड़ों से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी। खेती को बचाने के लिए और निवेश की जरूरत है।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

ब्लैक होल से डरकर एक तारा आकाशगंगा से भाग रहा

वाशिंगटन : ब्रह्मांड में एक अनूठी घटना सामने आई है। खगोलविदों को एक ऐसे तारे का पता चला है, जो ब्लैक होल से डरकर हमारी आकाशगंगा से बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। एस5-एचवीएस1 नामक यह तारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 40 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर जा रहा है। यह तारा इस समय धरती से करीब 29 हजार प्रकाश वर्ष दूर है।

महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सस्पेंस बढ़ा

सियासत ▶ सोनिया-पवार की मुलाकात के बाद और उलझ गया सत्ता का पेच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सस्पेंस और गहरा गया है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार की मुलाकात के बाद पेच खुलने के बजाय और उलझ गया। कांग्रेस-राकांपा के साथ जल्द सरकार गठन की शिवसेना की उम्मीदों के विपरीत पवार ने साफ कहा कि अभी तो कांग्रेस-राकांपा की मंत्रणा जारी है। पवार ने यह कहते हुए शिवसेना की धड़कनें और बढ़ा दी हैं कि सोनिया गांधी से तो सरकार के गठन को लेकर उनकी चर्चा ही नहीं हुई।

महाराष्ट्र में नई सरकार की कमान थामने की उम्मीद लगा रही शिवसेना के लिए कांग्रेस और एनसीपी का यह रुख झटके से कम नहीं है। शिवसेना के साथ-साथ कांग्रेस-राकांपा के नेताओं की निगाह भी सोनिया और पवार की बहुप्रतीक्षित बैठक पर लगी थी। मगर जब सोनिया से मुलाकात के बाद शरद पवार पत्रकारों से रूबरू हुए तो साफ कहा, अभी तो हम अपने सहयोगी दलों से ही बात कर रहे हैं।

शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस-राकांपा में सहमति के सवाल पर पवार ने कहा, सरकार गठन की बात है तो भाजपा-शिवसेना से पूछिए क्योंकि वे साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। शिवसेना की विचारधारा को लेकर सोनिया की आपत्ति सरकार बनाने में आड़े आने के सवाल को भी पवार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब कांग्रेस अध्यक्ष से सरकार गठन पर बात ही नहीं हुई तो यह सवाल कहां। उन्होंने यह जरूर कहा कि सियासी हालात पर दोनों पार्टियों की निगाह है और कांग्रेस-एनसीपी मिलकर भविष्य का कोई फैसला लेंगे।

कांग्रेस-राकांपा नेताओं में होगी चर्चा : पवार ने कहा, अगले कुछ दिनों में कांग्रेस-राकांपा के नेताओं की आपस में चर्चा होगी। दोनों पार्टियों का नेतृत्व अपने नेताओं की राय के अनुरूप आगे का सियासी रुख तय करेगा। बताया जा रहा है कि राकांपा की तरफ से अजीत पवार और जयंत पाटिल बातचीत का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस ने भी अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल को शामिल करते हुए एक कमेटी गठित की है। सूत्रों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण भी इस प्रक्रिया में शामिल रह सकते हैं।

कांग्रेस भी नहीं खोल रही पत्ते : महाराष्ट्र की सत्ता पर पवार के इस सस्पेंस को कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कायम रखा है। पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, शरद पवार ने सोनिया गांधी से भेंट में महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में जानकारी दी और तय किया गया कि दोनों दलों के नेता एक-दो दिन में दिल्ली में बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। कांग्रेस का यह सपाट बयान जाहिर कर रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी शिवसेना को सौंपने की दिशा में अभी कई पेच हैं।

पवार से मिलने पहुंचे राउत : शिवसेना नेता संजय राउत भी सोमवार देर शाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे। राउत का कहना है कि उन्होंने पवार से राज्य के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की अपील की है। यह प्रतिनिधिमंडल असमय बारिश से त्रस्त महाराष्ट्र के किसानों की स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराएगा।

बोले पवार

- भाजपा-शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा था, उनसे पूछिए सरकार गठन पर सवाल
- शिवसेना संग सरकार बनाने पर सोनिया से कोई चर्चा नहीं हुई, हालात पर है नजर

सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे राकांपा प्रमुख शरद पवार। प्रेट्र

राज्य में लगा है राष्ट्रपति शासन

उल्लेखनीय है कि नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद पर पेच फंसने के चलते शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था। इस कारण से विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 105 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाने के कारण भाजपा ने सरकार बनाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद से कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर शिवसेना सरकार बनाने की संभावना तलाश रही है। किसी पार्टी द्वारा बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण 12 नवंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।

आठवले ने भाजपा-शिवसेना को दिया नया फॉर्मूला

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के प्रमुख रामदास आठवले ने भाजपा और शिवसेना के बीच सरकार गठन का नया फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा, 'मैं संजय राउत से मिला और उनसे इस फॉर्मूला पर विचार करने को कहा कि तीन साल भाजपा का मुख्यमंत्री रहे और बाकी दो साल शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। राउत ने मुझे इस फॉर्मूला के बारे में भाजपा से बात करने को कहा है।' इससे पहले भी आठवले ने कहा था कि महाराष्ट्र में जल्द राजग सरकार बन जाएगी।

अयोध्या मुद्दे पर पुनर्विचार अर्जी की जरूरत नहीं : बुखारी

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने श्रीराम जन्मभूमि मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य जमातों के फैसले की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि देश के 95 फीसद से अधिक मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहते हैं। मात्र चंद लोग हैं जो मंदिर-मस्जिद का विवाद बनाए रखना चाहते हैं।

इस मुद्दे पर चल रही चर्चाओं के बीच बुखारी ने कहा कि मुख्य तौर पर चार बिंदुओं पर आपत्तियां थीं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुल्क के हालात के मद्देनजर सही फैसला सुनाया है। इसे दोनों धर्म के लोगों ने स्वीकार किया है। उन्होंने चेताया कि पुनर्विचार के फैसले से एक बार फिर समाज में तनाव दिखने लगा है। माहौल में फिर गर्मी आई है। यह खामोश लोगों को उकसाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वे जमाते हैं।

माहौल खराब करने की हो रही कोशिश : शाही इमाम ने कहा कि मस्जिद का मुकदमा लड़ने के नाम पर देश-विदेश से 7.5 करोड़ रुपये चंदे वसूले गए थे। अब फिर आगे यही होगा। उन्होंने कहा कि यही जमातें फैसला आने से पहले कहती थीं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वे उसे मानेंगी। अब जबकि फैसले को हिंदू-मुस्लिम सभी ने स्वीकार्य कर लिया है। देश में कहीं से भी तनाव या विवाद की खबरें नहीं आई हैं तो ये लोग एक बार फिर देश का माहौल खराब करने में लगे हैं।

फैसले को सभी ने स्वीकारा : शाही इमाम ने कहा कि 134 साल के बाद यह घड़ी आई जब यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला आने से पहले लोगों में डर का माहौल था कि देश की फिजा खराब हो जाएगी। इसलिए कई लोगों ने राशन खरीद लिए। कुछ तो अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां रहने चले गए। कुछ लोगों ने यात्राएं रद कर दीं। आखिरकार फैसला आया जिसको सभी ने स्वीकार्य करते हुए राहत की सांस ली। न हिंदू समाज में जोश दिखा, न ही मुस्लिम समाज ने प्रतिक्रिया दी।

- कहा, मंदिर-मस्जिद का विवाद बनाए रखना चाहते हैं चंद लोग

सैयद अहमद बुखारी फाइल फोटो

राज्यसभा को संतुलन के साथ चलना होगा : मोदी

राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के पहले दिन सदन में बोलते पीएम नरेंद्र मोदी। प्रेट्र (टीवी ग्रैब)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के 250वें सत्र को किया संबोधित
- विकास में केंद्र व राज्यों को सहभागी बनाने में रास की भूमिका को बताया अहम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार कहा कि लोकतंत्र में संसद के उच्च सदन में चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अहम है, लेकिन विरोध और अवरोध के बीच भेद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन उसे रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए।

राज्यसभा के 250वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सदन की प्रासंगिकता और उपयोगिता की प्रशंसा की। साथ ही आगाह भी किया कि संघीय ढांचे और विविधताओं से भरे होने के बावजूद राज्यसभा में राष्ट्रीय दृष्टिकोण ओझल नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि पिछले सत्र को छोड़ दिया जाए तो कई सत्रों में राज्यसभा सरकार के लिए बड़ी बाधा रही है, पिछले सरकार में उसके चलते कई अहम बिल अटक गए थे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की महत्ता का वर्णन किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा कि राज्यसभा दूसरा सदन जरूर है लेकिन दोयम नहीं, तो उन्होंने उसकी भूमिका का भी अहसास कराया।

प्रधानमंत्री ने कहा, राज्यों का प्रतिनिधित्व होने के कारण राज्यसभा यह सुनिश्चित करती है कि केंद्रीय नीतियों में राज्यों के हितों की अनदेखी नहीं होने पाए। उन्होंने कहा कि उच्च सदन के एक और लाभ है। राजनीतिक परिस्थितियों के चलते हर कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाता। लेकिन राष्ट्रहित में उनकी उपयोगिता बहुत अहम होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर हैं। लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाने के बावजूद उन्होंने राज्यसभा में रहते हुए देश के लिए अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा ने संसद के निचले सदन में कमजोर विपक्ष के जमाने में सरकार पर अंकुश लगाने का काम भी किया है। प्रधानमंत्री ने तीन तलाक और जीएसटी पर कानून बनाने और अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35ए के प्रावधानों को खत्म कराने में राज्यसभा के योगदान की भी सराहना की।

मनमोहन ने राज्यसभा की बड़ी भूमिका पर दिया जोर : चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जम्मू-कश्मीर का नाम लिए बिना राज्यों के सीमा-निर्धारण में राज्यसभा की बड़ी व अहम भूमिका की जरूरत बताई। इसके साथ ही उन्होंने विधेयकों को स्थायी व प्रवर समितियों में भेजे बिना ही संख्याबल के दम पर सदन से पास कराने की मानसिकता को गलत बताया। उनका कहना था कि समितियों में व्यापक विचार-विमर्श से विधेयकों को मुकम्मल बनाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने विधेयकों को मनी बिल की श्रेणी में बिना राज्यसभा की सहमति के पास कराने की कोशिशों पर भी आपत्ति जताई।

प्रधानमंत्री ने की राकांपा की तारीफ पेज>>3

नागरिकता संशोधन बिल में कुछ बदलाव कर सकती है सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन बिल के विरोध को देखते हुए सरकार इसमें कुछ बदलाव कर नए प्रावधान जोड़ सकती है। नए बिल में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि कौन अवैध घुसपैठिए हैं और कौन धार्मिक उत्पीड़न के चलते पड़ोसी देशों से भागकर आए शरणार्थी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ज्ञात हो, नागरिकता संशोधन बिल, 2018 में पिछली लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। पिछली लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही यह बिल भी खत्म हो गया था। अब सरकार फिर इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी में है। इस बिल के जरिए नागरिकता विधेयक, 1955 में संशोधन किया जाना है, ताकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को बिना पर्याप्त दस्तावेज के भी भारतीय नागरिकता मिल सके।

प्रदूषण फैलाने वालों को मिलेगी सजा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवरों को देखते हुए अब केंद्र सरकार भी सख्ती की तैयारी में है। सोमवार को इस संबंध में पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों समेत दूसरे विभागों के आला अफसरों की बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में साफ कहा है कि प्रदूषण पर रोकथाम के नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हर किसी की जवाबदेही व जिम्मेदारी तय होगी। सजा भी दी जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के इन कड़े तेवरों को फिलहाल 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर होने वाली सुनवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, मंगलवार को लोकसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा होनी है।

पर्यावरण सचिव सीके मिश्रा ने कहा, बैठक में प्रदूषण पर रोकथाम के एक्शन प्लान की समीक्षा की गई। सभी राज्यों व जिम्मेदार एजेंसियों से ब्योरा लिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की ओर से जारी निर्देशों के अमल की समीक्षा की गई है। ज्यादातर राज्य गंभीरता से काम कर रहे हैं। हालांकि पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक भले ही नहीं लग पाई है, लेकिन पंजाब व हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले कमी आई है।

मिश्रा ने कहा, बैठक में प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष अभियान शुरू करने पर सहमति बनी है। राज्य और अन्य एजेंसियां मिलकर अगले 15 दिन तक यह अभियान चलाएंगी। बाद में अभियान 31 दिसंबर तक जारी रखा जाएगा। इस दौरान पानी के छिड़काव समेत प्रदूषण रोकने के सभी जरूरी उपायों को सख्ती से अपनाया जाएगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम के डीएम भी शामिल हुए। दिल्ली के मुख्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी व सभी नगर निगमों के आयुक्त मंत्रालय पहुंचे थे।

अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में नहीं दिखेगा एक भी खुला क्षेत्र : दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में धूल की बढ़ी हुई मात्रा को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है। इसके तहत अगस्त, 2020 तक दिल्ली-एनसीआर में खुली पड़ी सारी जमीन को या तो हरा-भरा कर दिया जाएगा या इंटरलॉकिंग से ढंक दिया जाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उप्र के मुख्य सचिवों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं।

दिल्ली और एनसीआर में बढ़े प्रदूषण पर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में पर्यावरण सचिव के कड़े तेवर

नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण सचिव सीके मिश्रा की अध्यक्षता में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रेट्र

सियाचिन में हिमस्खलन, चार जवान और दो पोर्टर शहीद

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- बीमार साथी को अस्पताल पहुंचाने के लिए निकले थे जवान और पोर्टर

उत्तरी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे युद्धस्थल सियाचिन में करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई पर सोमवार दोपहर बाद हुए हिमस्खलन की चपेट में आकर सेना के चार जवान और दो पोर्टर शहीद हो गए। अस्पताल में भर्ती एक जवान की हालत गंभीर है। यह दल अपने बीमार साथी को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास कर रहा था कि हिमस्खलन की चपेट में आ गया।

सैन्य अधिकारियों के अनुसार, सियाचिन में माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में नियंत्रण रेखा के पास पेट्रोलिंग कर रही सेना की टुकड़ी सोमवार दोपहर बाद हिमस्खलन की चपेट में आ गई। बचाव के लिए एवलांच पैंथर्स और माउंटेन रेस्क्यू टीम को भेजा गया। टीम ने जवानों को खोज निकाला। छह जवानों और दो पोर्टरों को हेलीकॉप्टर से सैन्य अस्पताल ले जाया गया। इनमें चार जवान और दो पोर्टर हाइपोथर्मिया के कारण शहीद हो गए। ज्ञात हो, फरवरी 2016 में भी सियाचिन में सेना की एक चौकी के हिमस्खलन की चपेट में आने से सेना के दस जवान शहीद हो गए थे।

क्या है हाइपोथर्मिया : अल्पताप (हाइपोथर्मिया) में शरीर का तापमान सामान्य से काफी कम हो जाता है। सामान्य तौर पर शरीर का तापमान 37 डिग्री (98.6 फारनाइट) रहता है। बहुत अधिक ठंडे वातावरण के कारण यह 35 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इस स्थिति को अल्पताप कहते हैं। सियाचिन में तापमान शून्य से 30 डिग्री से भी नीचे रहता है। ऐसे में वहां शरीर का तापमान तेजी से नीचे गिरता है।

1984 में हुई थी सेना की तैनाती : भारत ने 1984 में सियाचिन में सेना की तैनाती शुरू की थी। दरअसल, पाक की ओर से सैनिकों को भेजकर यहां कब्जे की कोशिश की गई थी। इसके बाद से जवानों की तैनाती रही है।

सड़क पर उतरे जेएनयू छात्र, आठ घंटे चला हंगामा

- विश्वविद्यालय से संसद तक निकाला मार्च, कई मार्गों पर लगा जाम
- छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को दो बार करना पड़ा बल-प्रयोग

नई दिल्ली में सोमवार को जेएनयू हॉस्टल की फीस वृद्धि को लेकर संसद तक मार्च निकाल रहे छात्रों को आगे बढ़ने से रोकते पुलिसकर्मी। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हॉस्टल (छात्रावास) की फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र-छात्राएं सोमवार को सड़क पर उतर आए। जेएनयू से संसद तक मार्च निकालने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने करीब आठ घंटे तक राजधानी में हंगामा चलता रहा। पुलिस ने उन्हें अरबिंदो मार्ग पर सफदरजंग मकबरे के पास रोका तो हजारों छात्र सड़क पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को शाम तीन बजे और रात सवा सात बजे बल प्रयोग करना पड़ा। छात्र मांग कर रहे थे कि कुलपति उनसे बात कर फीस वृद्धि वापस लें।

संसद सत्र के पहले ही दिन सोमवार को जेएनयू के छात्रों ने कैंपस से संसद तक पैदल मार्च निकालकर अपनी आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तक पहुंचाने का एलान किया था। सोमवार सुबह 10 बजे से ही छात्र कैंपस में एकत्र होने लगे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने सुबह ही जेएनयू के नॉर्थ गेट को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया था। क्षेत्र में धारा 144 लगा दी थी। इसके बावजूद दोपहर 12 बजे सैकड़ों छात्र बाबा गंगनाथ मार्ग होते हुए कटवरिया सराय की ओर बढ़े। यहां लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ कर छात्र आगे बढ़ने लगे। इस पर 150 छात्र-छात्राओं को हिरासत में लेकर बस से बदरपुर, कालकाजी, कैंट, फतेहपुरबेरी व सरोजनी नगर थाने में ले जाया गया।

पुलिस के मुताबिक, जेएनयू से संसद मार्ग तक पैदल मार्च निकालने की अनुमति नहीं थी। जेएनयू और पूरे नई दिल्ली इलाके में धारा-144 लगी थी। इसके बावजूद हजारों छात्रों ने जेएनयू के बाहर लगाए गए तीनों बैरिकेड को तोड़ दिया। तीसरा बैरिकेड तोड़ने वाले छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो उन्होंने मार्ग बदल लिया। अब प्रदर्शनकारी नेल्सन मंडेला मार्ग से मुनिरका, स्वामी विवेकानंद मार्ग होते हुए हयात होटल के सामने से रिंग रोड पर आ गए। भीकाजी कामा, सरोजनी नगर व एम्स फ्लाइओवर होते हुए छात्र अरबिंदो मार्ग पर सफदजंग मकबरे के पास पहुंए गए।

यहां पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए। बताया गया कि छह आंदोलनकारियों के सिर में चोट आई है। भारी संख्या में पुलिस बल बुलाकर छात्रों को अरबिंदो मार्ग पर ही रोक दिया गया। इस पर छात्र वहीं धरने पर बैठ गए। एहतियातन जोरबाग मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। समझाने के तमाम प्रयास विफल होने पर शाम सात बजे फिर बल प्रयोग किया गया। इसमें दो दर्जन छात्र-छात्राओं को चोटें आई हैं।

छात्रों ने पुलिस को दी नसीहत पेज>>2
शांति बहाली के लिए उतरा केंद्र पेज>>2

बदलाव

उच्च सदन के ऐतिहासिक 250वें सत्र का पहला दिन, सदन में आसन के दाएं-बाएं खड़े होने वाले सहायकों की बदल गई पोशाक, सचिवालय ने कहा, लंबे समय से पुरानी ड्रेस को बदलने की हो रही थी मांग

राज्यसभा में सैनिक की पोशाक में दिखे मार्शल, चकित हुए सदस्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के पहले ही दिन सदन के भीतर तैनात होने वाले मार्शलों की नई पोशाक ने सांसदों को चौंका दिया। सैनिकों की तरह पोशाक पहने आसन के दोनों तरफ तैनात मार्शल को देख सांसदों ने अचरज और कौतूहल में सभापति वेंकैया नायडू से सैन्य पोशाक को लेकर सवाल उठाने का भी प्रयास किया, मगर नायडू ने इसकी अनुमति नहीं दी।

सभापति ने सदन के दिवंगत सदस्यों के प्रति जैसे ही अपनी संवेदना जताई, वैसे ही कुछ सदस्यों ने कौतूहल में आसन से पूछा- क्या नई पोशाक में तैनात सहायक मार्शल हैं? नायडू ने इस पर कहा कि -हां ये मार्शल हैं, मगर कोई सदस्य कुछ कहे इससे पहले उन्होंने अरुण जेटली समेत अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बोलने की पहल शुरू करा दी।

जब करीब घंटे भर बाद नेताओं के संवेदना जताने का सिलसिला थमा तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मार्शलों की सैनिकों जैसी पोशाक को लेकर सवाल उठाने का प्रयास किया, मगर सभापति ने उनके सवाल को तत्काल खारिज करते हुए सदन को स्थगित कर दिया। राज्यसभा सचिवालय ने मार्शलों की नई पोशाक पर यह कहते हुए तस्वीर साफ करने का प्रयास किया कि बहुत लंबे समय से सभापति के दाएं -बाएं तैनात रहने वाले सहायक अपनी पुरानी ड्रेस को बदलने की मांग करते आ रहे थे।

राज्यसभा में सोमवार को सभापति एम वेंकैया नायडू के आसन के दाएं-बाएं सैनिकों जैसी पोशाक में मार्शल (ऊपरी तस्वीर)। इसके पहले मार्शल की पोशाक ऐसी हुआ करती थी (नीचे की तस्वीर)। एएनआइ

अब ऐसी हुई पोशाक

सोमवार को मार्शलों के सिर पर पगड़ी की बजाय गहरे हरे रंग की 'पी-कैप' थी। साथ ही उन्होंने गहरे हरे रंग की सैनिकों जैसी वर्दी धारण कर रखी थी। राज्यसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि मार्शलों की सैनिकों जैसी यह नई पोशाक स्थायी रूप से रहेगी। हालांकि गर्मियों के मौसम में इसका रंग जरूर बदलकर सफेद हो जाएगा। सभापति वेंकैया नायडू ने इस नई पोशाक की डिजाइन और रंग को मंजूरी दे दी है।

पहले यह थी पोशाक

इस नई पोशाक से पहले इन सहायकों का ड्रेस सामान्य था और सिर पर अंग्रेजों के समय से चली आ रही सहायकों वाली पगड़ीनुमा टोपी रहती थी। सभापति सहित अन्य पीठासीन अधिकारियों की सहायता के लिए लगभग आधा दर्जन मार्शल तैनात होते हैं। मार्शलों ने उनके ड्रेस कोड में बदलाव कर ऐसी पोशाक शामिल करने की मांग की थी जो पहनने में सुगम हो।